

रूस को 'आतंकवाद के राज्य प्रायोजक' के रूप में नामति करने का अनुरोध

प्रलिम्स के लिये:

रूस का स्थान, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, यूएनएचआरसी, यूएनएससी ।

मेंन्स के लिये:

भारत के हतियों पर देशों की नीतियों और राजनीतिका प्रभाव, रूस-यूक्रेन संघर्ष और वैश्विक भू-राजनीतपर इसका प्रभाव ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में यूक्रेन ने अमेरिका से रूस को "आतंकवाद के राज्य प्रायोजक" के रूप में नामति करने का अनुरोध किया है ।

- इसके परिणामस्वरूप रूस के खिलाफ अमेरिका के पास उपलब्ध सभी प्रतिबंधों में से सबसे कठोर प्रतिबंध लगाए जा सकेंगे ।



आतंकवाद के राज्य प्रायोजक से तात्पर्य

परचिय:

- इसके तहत अमेरिकी वदिश मंत्रि के पास "आतंकवाद के राज्य प्रायोजक" के रूप में "अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के कृत्यों के लिये बार-बार समर्थन प्रदान करने वाले देशों" को नामति करने की शक्ति होती है ।
- अमेरिका इस सूची में शामिल देशों पर चार तरह के प्रतिबंध लगा सकता है:
 - अमेरिकी वदिशी सहायता पर प्रतिबंध
 - रक्षा नरियात और बकिरी पर प्रतिबंध
 - दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के नरियात पर कुछ नयितरण
 - वविधि वतितीय और अन्य प्रतिबंध
- इसके तहत उन देशों और व्यक्तियों पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं जो नरिदष्ट देशों के साथ व्यापार में संलग्न हैं ।

इस सूची में शामिल देश:

- अब तक आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों की सूची में चार देश हैं:
 - सीरिया (29 दसिंबर 1979 को नामति)
 - ईरान (19 जनवरी 1984 को नामति),

- उत्तर कोरिया (20 नवंबर 2017 को नामति)।
- 12 जनवरी 2021 को [क्यूबा को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक](#) के रूप में दोबारा नामति किया गया था।

आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में नामांकन वाले कानून

- वर्तमान में तीन कानून हैं जो वदेशि मंत्री को अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के कृत्यों के लिये बार-बार समर्थन प्रदान करने हेतु एक देश को नामति करने के लिये अधिकृत करते हैं:
 - **1961 का वदेशि सहायता अधिनियम:** यह अधिकांश सहायता के हस्तांतरण पर रोक लगाता है;
 - **शस्त्र नरियात नयितरण अधिनियम (AECA):** यह नरियात, क्रेडिट, गारंटी, अन्य वित्तीय सहायता और राज्य वभिग द्वारा नयितरति नरियात लाइसेंसिंग को प्रतबिंधति करता है; और
 - **2018 का नरियात नयितरण अधिनियम**
- इन तीन कानूनों में से केवल AECA ही आपत्तजनिक गतिविधियों को आतंकवाद के रूप में सीमति स्तर परभिषति करती है, जबकि तीनों अधिनियमों में से कोई भी "अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद" को व्यापक अर्थ में परभिषति नहीं करता है।

रूस-यूक्रेन संघर्ष पर भारत का क्या रुख रहा है?

- प्रारंभ में भारत अमेरिका द्वारा प्रायोजति [संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद \(यूएनएससी\)](#) के उस प्रस्ताव में अनुपस्थिति रहा जिसमें यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता की कड़ी नदि की गई।
- भारत ने यूक्रेन में मानवीय स्थिति पर रूस द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव पर यूएनएससी में मतदान में भी अनुपस्थिति रहा, जिसमें नागरिकों की सुरक्षति, तीव्र, सवैच्छिक और नरिबाध नकिासी को सकषम करने के लिये बातचीत के जरिए संघर्ष वरिम का आह्वान करने की मांग की गई थी।
 - यूक्रेन से संबंधति पछिली अनुपस्थिति के वपिरीत, यह पहली बार था कि **भारत ने इस संघर्ष में पश्चिमि का साथ दिया**।
- भारत जनिवा में [संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद](#) में मतदान से दूर रहा। परिषद ने यूक्रेन में रूस की कार्रवाइयों की जाँच के लिये एक अंतरराष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रस्ताव पेश किया।
- भारत, चीन और 33 अन्य देशों की हाल ही में [संयुक्त राष्ट्र महासभा](#) के उस प्रस्ताव में अनुपस्थिति रही से जिसमें यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई हेतु उसकी नदि की गई थी।
- भारत ने [अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी \(IAEA\)](#) के प्रस्ताव से भी अनुपस्थिति रहा जो चार परमाणु ऊर्जा स्टेशनों और [चेरनोबलि](#) सहति कई परमाणु अपशष्टि स्थलों पर सुरक्षा से संबंधति था, क्योंकि रूस द्वारा उन पर नयितरण कर लिया था।

आगे की राह:

- यूक्रेन पर रूस का हमला, हालाँकि [अंतरराष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन है, इस एक प्रकार का आतंकवादी प्रयोजनों](#) नहीं है, लेकिन रूस ने इसके लिये पछिले एक दशक में आतंकवादी प्रयोजनों के संबंध में कई अन्य आधार प्रदान किये हैं।
 - कसी देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में नामति करने के लिये वदेशि मंत्री को यह नरिधारति करना होगा कि देश की सरकार ने बार-बार अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के कृत्यों जैसे कि हित्या या आतंकवादी समूहों को वतितपोषण के लिये समर्थन प्रदान किया है।
- भारत के दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध हैं। यद [दोनों अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ता](#) है तो भारत के लिये रशितों को तरकसंगत रूप से संतुलति करना महत्त्वपूर्ण है।
 - रूस के साथ भारत के संबंध उतने बहुआयामी नहीं हैं जतिने कि [अमेरिका, यूरोप या जापान](#) के साथ भारत के संबंध हैं। रूस के साथ भारत के संबंध मुख्य रूप से ऊर्जा और रक्षा पर केंद्रति हैं।
 - [भारत-रूस द्वपिक्षीय व्यापार केवल 11 बलियन अमेरिकी डॉलर](#) का है, लेकिन रूसी सैन्य उपकरणों की भारतीय खरीद इसका सबसे महत्त्वपूर्ण तत्व है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस